

प्रेषक,

कुंवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

प्रेषण अनुभाग-III

देहरादून। दिनांक 3। मार्च, 2007

विषय:-

देहरादून नगर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में मिनी नलकूप/पाइप लाइन विस्तार
कार्यो हेतु वर्ष 2007-08 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 5806/2006-07 दिनांक 26.03.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून नगर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में मिनी नलकूप/पाइप लाइन विस्तार कार्यो हेतु प्राप्त कराये गये निम्न योजनाओं के प्राक्कलनों पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल रु0 118.95 लाख की धनराशि के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही उनके सम्मुख अंकित निम्नविवरणानुसार कालम संख्या-5 में उल्लिखित कुल धनराशि रु0 107.65 (रुपये एक करोड़ सात लाख पैंसठ हजार मात्र) के व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	मांग की गयी धनराशि	औचित्यपूर्ण पायी धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	02	03	04	05
01	मंदाकिनी बिहार, अर्धाईवाला में मिनी नलकूप का निर्माण	22.13	20.90	20.90
02	कैनाल रोड़ जाखन में पाइप लाइन बदलने का प्राक्कलन	12.54	11.85	11.85
03	धुच्चुपानी में 2 मिनी ट्यूबवैल का निर्माण	72.675	55.90	44.60
04	सालावाला में मिनी नलकूप का खनन कार्य	22.17	21.80	21.80
05	मेघदूत एन्कलेव कालीदास रोड़ से डोभालवाला अपर अभावग्रस्त क्षेत्र में पाइप लाइन का विस्तार कार्य	9.55	8.50	8.50
	योग	107.65	118.95	107.65

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही किशतों में किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

12

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्वेत्ता के साथ अवश्य करा लें। स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाये।
11. जी०पी०डब्ल्यू० फार्म ९ की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
12. उक्त स्वीकृत धनराशि में उल्लिखित नगरीय पेयजल योजनाओं का सुदृढीकरण उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। योजनावार स्वीकृत धनराशि के सम्बन्धित शाखा को आवंटन की सूचना धनराशि आहरण के एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
13. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या ए-2-87(1) दस-97-17(4)/76 दिनांक 27-02-97 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।
14. कार्य उक्त लागत में निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इस लागत में किसी भी प्रकार का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशारी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

16. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-“2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत- 101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-03-नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता” के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 82/XXVII(2)/ 07 दिनांक 21 मई, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

प्र0सं0 793 /उन्तीस(2)/07-(22पे0)/2007 तदुदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल।
9. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव